

प्रेषक

मनीषा मंगार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,

हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 07-मई, 2009

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में अनुसूचित जनजाति विभाग में बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना के अंतर्गत अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 (01 अप्रैल 2009 से 31 जून 2009 तक) के आय-व्ययक में अनुसूचित जनजाति व. बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना के अनुदान संख्या-31 के रुपये 86,67,000 (रुपये छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) आयोजनागत पक्ष की प्राविधानित धनराशियों में से राज्य सरकार के अनुसार जनजाति का चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में उल्लिखित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपको निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (ट्रिगास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशपलो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह दैनिक आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्पाही से अनुदान संख्या-30 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो मांग का औचित्य प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रविधानों के अंतर्गत सन्ध-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
11. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएँ।
12. बी०एम०-13 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. छठे वेतन आयोग की संस्तुति के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नहीं किया जायेगा। तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारण वश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सेवानिवृत्त होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कर्मिकों के सम्बन्ध में नहीं रहेगा।
14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेंट रूलस 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
15. बात जल्दबाजी है कि शासन के व्यय में निवृत्तित्व नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय निवृत्तित्व का सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
16. दृष्टांत में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 37 (P)/XXVII(3)/2009-10 दिनांक 28 अप्रैल 2009 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: संख्या:-457/XVII-1/2009-10(41)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 निजी सचिव मा0 समाज कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड विधान सभा देहरादून।
- 3 निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5 मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं उत्तराखण्ड।
- 6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7 निदेशक, कौषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8 वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून।
- 9 सनस्ता कौषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10 समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
- 12 समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- 13 बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15 आदेश पत्रिका।

अज्ञा सं.

(Signature)

(धीरेन्द्र सिंह/दत्ताल)

उप सचिव।